

सीएसआईआर-यूजीसी-नेट की परीक्षा स्थगित

25-27 जून के बीच होना था एग्जाम; एनटीए ने संसाधनों की कमी को वजह बताया

एनटीए ने शुक्रवार को शाम 8.30 बजे सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा स्थगित कर दी। यह एग्जाम 25-27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सों की कमी बताई गई है। साथ ही एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csimnet.nta.ac.in पर की जाएगी। दो दिन पहले 19 जून को गडबडियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द की थी।



इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसिलिंग पर रोक लगाने से फिर एक बार इनकार कर दिया है। एक स्टूडेंट ने

सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। स्टूडेंट का कहना था कि 773 कैडेट्स बिना प्रेस मार्क्स पाए फेल हुए हैं। पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। 8 जुलाई को केंस पर सुनवाई होनी है ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसिलिंग भी 2 दिनों आगे बढ़ाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, रीएग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।

एंटी-पेपर लीक कानून लागू

आधी रात को अधिसूचना जारी; पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल सजा, 10 लाख तक जुर्माना

दिल्ली। देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार (21 जून) की आधी रात इसकी अधिसूचना जारी की। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गडबडियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत, पेपर लीक करने या ऑफर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए



नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक

जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है, तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाओं में गडबडियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम है। इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गडबडी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति मुर्मू ने 12 फरवरी को कानून को मजूरी दी थी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन

ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

P-3
वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाने में हो रही



P-4
मंदिर के दीये से लगी आग, कारोबारी का बेटा जिंदा जला



P-5
सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तान समर्थकों को कनाडा की संसद में



P-6
विदेश मंत्रालय ने किया साफ, हज यात्र के दौरान कम से कम 98 भारतीय

143 मौतें, 41 हजार से ज्यादा बीमार; देशभर में हीटस्ट्रोक से हाहाकार

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि देश के बड़े हिस्से में लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी ने कई लोगों की जान ले ली है। इस साल 1 मार्च से 20 जून के बीच 143 लोगों की मौत हुई है और 41,789 लोग संदिग्ध हीटस्ट्रोक से पीड़ित हैं। हालांकि, हीटवेव से मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है, क्योंकि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा राष्ट्रीय हीट-संबंधित बीमारी और मृत्यु निगरानी के तहत संकलित आंकड़ों में राज्यों से अद्यतन जानकारी नहीं है। कई स्वास्थ्य सुविधाओं ने अभी तक हीटवेव से मरने वालों की संख्या के



बारे में डेटा अपलोड नहीं किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 20 जून को ही हीटस्ट्रोक के कारण 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और संदिग्ध हीटस्ट्रोक के कारण नौ लोगों की मौत हुई, जिससे मार्च-जून की अवधि में मरने वालों की संख्या 114 से बढ़कर 143 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक

या नहीं और साथ ही पिछले कुछ दिनों में लू लगने से हुई मौतों की संख्या का भी आकलन किया जा सके। उत्तरी और पूर्वी भारत के कई हिस्से लंबे समय से लू की चपेट में हैं, जिससे लू लगने से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है और केंद्र ने अस्पतालों को ऐसे मरीजों के इलाज के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने का परामर्श जारी किया है। उत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाके लंबे समय से लू की चपेट में हैं, जिससे हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है और केंद्र ने अस्पतालों को ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने के लिए सलाह जारी की है।

असम में गंभीर हुई बाढ़ की स्थिति, चार लाख लोग प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति शुक्रवार को भी गंभीर बनी रही। प्रमुख नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ से चार लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आई है। इधर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य सरकार से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की अपील की। साथ ही मृतकों के स्वजन को मुआवजा देने की मांग भी की है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य की कोपिली, बराक और कुशियारा जैसी



कुछ प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं हैं। 36 लोगों की मौत राज्य के 19 जिलों में चार लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीमगंज में सबसे ज्यादा 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके बाद बाढ़ प्रभावितों में दरंग और तामुलपुर का स्थान है। बाढ़, भूस्खलन और तूफान से राज्य में जान गवाने वालों की संख्या 36 हो गई है।

रिहाई पर रोक राऊज एवम् स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी

अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

एजेंसी
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से निचली अदालत के श्री केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम

पीठ के समक्ष ईडी का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जबकि मुख्यमंत्री का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने रखा
आदेश पारित किया। पीठ के समक्ष ईडी का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जबकि मुख्यमंत्री का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने रखा। न्यायमूर्ति जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार पूर्वक सुनने के बाद श्री केजरीवाल को जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि इस मामले में अगले दो-तीन दिनों में

विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी उन्होंने ने कहा, मैं आदेश को दो से तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ। आदेश की घोषणा तक निचली अदालत के आदेश के क्रियाव्यवहन पर रोक है। इससे पहले उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी की

न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। कल देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। पीठ के समक्ष ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री की रिहाई पर रोक लगाने और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि ईडी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

मोदी ने दिल्ली का पानी बंद कर दिया : संजय सिंह

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए शुक्रवार को कहा कि दिल्ली की जनता ने जिस दिन से प्रधानमंत्री ने दिल्लीवालों का पानी रुकवा दिया। जलमंत्रि आतिशो द्वारा शुरू किए गए 'पानी सत्याग्रह' स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आज कहा, "हमारे देश में मान्यता है कि पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। इस भीषण गर्मी में हम छोटे-छोटे पंथियों के लिए अपने घरों पर पानी रखते हैं। हमारे समाज की मान्यता है कि कोई भी



जीव-जंतु प्यासा न रहे और इसके लिए जो भी संभव हो करना चाहिए लेकिन भाजपा के अंदर इतनी क्रूरता और निर्दयता है कि वह दिल्ली में लोगों को पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसा रही है। देश में हर राज्य के लिए पानी की व्यवस्था बनाई गई है। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है और हरियाणा को यह पानी पंजाब से मिलता है।



हैप्पी मॉर्निंग
मॉल में बिस्कुट चोरी करते हुए एक खूबसूरत महिला पकड़ी गई और फिर... जज- तुमने बिस्कुट का एक पैकेट चुराया, जिसमें 30 बिस्कुट थे, इसके लिए तुम्हें 30 दिनों की सजा सुनाई जाती है महिला का पति बोला- जज साहब, सूजी का पैकेट भी चुराया है।



शायरी
मत मारो गोलियों से मुझे मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ, मेरी मौत कि वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ

अर्थसार
सेंसेक्स: 77,209.90
-269.03 (0.35%)
निफ्टी: 23,501.10
-65.90

मौसम
अधिकतम : 39 डिग्री से 0 न्यूनतम : 31 डिग्री से
सूयोदय रविवार : 5 : 26
सूर्यास्त शनिवार : 7 : 27

तमिलनाडु शराब कांड : जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 47 हुई

इनमें से 24 एक गांव के, एक साथ कई चिताएं जलीं; 30 की हालत अब भी गंभीर

कल्लकुरिची। तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। इनमें से 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। चिकित्सा शिक्षा निदेशक जे. संगुमनी के मुताबिक अभी भी 30 की हालत गंभीर बताई गई है। उधर, शराब कांड के तीन आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन्हें कडुलोर जेल में रखा गया है। तीनों आरोपी 5 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे। जहरीली शराब के कारण अपने बेटे को खोने वाली एक महिला ने रोते हुए बताया कि बेटे को पेट में बहुत दर्द था। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। जब हम उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो शुरुआत में उसे भर्ती भी नहीं किया गया था। कहा गया था कि बेटा नशे में है। बाद में बेटे की जान चली गई। महिला ने आगे कहा कि सरकार को शराब की दुकानें



बंद कर देनी चाहिए। 100 से ज्यादा पीड़ितों का कल्लकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा दूसरे अस्पतालों में इलाज जारी है। सभी को सांस लेने में दिक्कत, कम दिखाई देने और शरीर में तेज दर्द की शिकायत है। अन्नामलाई ने शाह को लेटर लिखा, सीबीआई जांच की मांग की कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कल्लकुरिची की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं, राज्य सरकार घटना की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे चुकी है। अन्नामलाई ने लेटर में लिखा, कई

INVEST IN REAL ESTATE

Choose the Best Investment Option In today's Volatile Market condition & Earn High capital Growth

INVEST IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL PROPERTY NEAR JEWAR AIRPORT

Commercial & Residential Property near Noida/Jewar International Airport at Yamuna Expressway.

[CONTACT NOW](#)

संपादकीय



सच्ची मर्दानगी : जब महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करतीं, तो आप मर्द नहीं

जिसे समझा था हमने अपना, वो ही बन गया दुश्मन, जब महिला को सुरक्षा न दे पाए, वो मर्द नहीं, बस एक भ्रम।



जितेंद्र चौधरी, प्रधान संपादक, विशाल इंडिया हिंदी दैनिक

हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। एक सच्चे मर्द की पहचान उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशीलता और सुरक्षा देने की क्षमता से होती है। अगर कोई लड़की या औरत आपके साथ खुद को सुरक्षित नहीं समझती है, तो यह आपकी मर्दानगी पर सवाल खड़ा करता है।

महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता

महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं को हर दिन घर, सड़क, कार्यस्थल और यहां तक कि अपने ही परिवार में भी असुरक्षित महसूस करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल हमारे समाज की कमजोरी को दर्शाती है, बल्कि यह हमारी मर्दानगी पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।

सच्ची मर्दानगी की परिभाषा

सच्ची मर्दानगी का मतलब है महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता का संरक्षण। एक सच्चा मर्द वही है जो महिलाओं को अपने बराबर का स्थान दे और उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। अगर एक मर्द अपने आसपास की महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता, तो उसकी मर्दानगी केवल नाममात्र की है।

शायरी

मर्द वही है जो हर हाल में रखे इज्जत और सम्मान, जिसके साथ हो हर नारी, खुद को समझे महफूज़ और सुकून भरा जहान। अगर ना दे सके सुरक्षा और स्नेह का अहसास, तो क्या मर्दानगी, वो है बस एक झूठा दावा और विश्वास।

समाज की भूमिका

समाज का हर व्यक्ति इस बदलाव में योगदान दे सकता है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार को सुधारना होगा। यह जिम्मेदारी केवल पुरुषों की नहीं है, बल्कि समाज के हर सदस्य की है कि वे महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का वातावरण प्रदान करें।

कानून और नीतियों का पालन

सरकार और कानून व्यवस्था को भी इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने होंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को आवश्यकता है। इसके अलावा, समाज में जागरूकता फैलाने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

पुरुषों की जिम्मेदारी

पुरुषों को यह समझना होगा कि उनकी मर्दानगी केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और महिलाओं के प्रति उनके सम्मान में है। उन्हें महिलाओं के साथ सहयोग और समझदारी से पेश आना चाहिए और उनकी सुरक्षा का जिम्मा लेना चाहिए।

प्रेरणादायक दृष्टिकोण

मर्दानगी का मतलब है नारी को मान-सम्मान, जिसके साथ हो हर महिला, खुद को समझे महफूज़ और सुकून भरा जहान।

अगर ना दे सके सुरक्षा और स्नेह का अहसास, तो क्या मर्दानगी, वो है बस एक झूठा दावा और विश्वास।

निष्कर्ष

अगर कोई लड़की या औरत आपके साथ खुद को सुरक्षित नहीं समझती है, तो यह आपकी मर्दानगी पर एक गंभीर सवाल है। हमें अपने समाज को ऐसा बनाना होगा जहां हर महिला खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। सच्ची मर्दानगी का अर्थ है महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करना।

जो देता है सम्मान, वही है सच्चा मर्द, जो रखे महिला को सुरक्षित, उसका है असली गर्व। अगर न दे सके सुरक्षा का अहसास, तो मर्दानगी का दावा है बस एक झूठा विश्वास।

बेजुबान जानवरों की भी फिक्र हो

वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 तो सबसे गर्म वर्ष माना ही गया, मगर 2024 में स्थिति और भी विकट लग रही है। भारतीय मौसम विभाग की पूर्व में दी गई चेतावनी सच साबित हो रही है और चरम हॉटवेव या गर्म लहरों से भारत का अधिकांश हिस्सा झुलस रहा है।

इस साल दिल्ली कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में बीएसएफ के एक जवान द्वारा रेत में पापड़ तलने का वायरल वीडियो सारे देश ने देखा। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) के अनुमान के अनुसार, गर्मी से जून की शुरुआत तक देश में कम से कम 219 लोगों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये गर्म लहरें अब लंबी, तीव्र और लगातार होती जाएंगी। ये विकट परिस्थितियां वन्यजीवों तथा पादप प्रजातियों के लिए भी समान रूप से घातक हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह स्थिति निरंतर गहरा रही है। असहनीय गर्मी से मनुष्यों के साथ ही जीव-जंतुओं की मौतें भी बढ़ रही हैं। हिमालय से लेकर महासागर तक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की जीव और पादप प्रजातियां रहती हैं। इनमें कुछ जीव और पादप ऐसे हैं, जो अत्यंत ठंडे या बर्फीले इलाके में रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, जो गर्म इलाकों में जीवित रह सकते हैं। लेकिन गर्मी और ठंड के संतुलन को जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें गड़बड़ी या असंतुलन हो जाने से जीवधारियों के साथ ही पादपों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है।

गर्मी बेजुबान वन्यजीवों के लिए गंभीर संकट पैदा करती है। कई जानवर, विशेष रूप से वे, जो अत्यधिक गर्मी के अनुकूल नहीं हैं, अधिक गर्मी से पीड़ित होते हैं। अत्यधिक गर्मी से निर्जलीकरण और हाइपरथर्मिया जैसी समस्याओं से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। वन्यजीव अक्सर गर्मी से बचने के लिए रात में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनके भोजन और सहवास का पैटर्न बाधित हो सकता है। जल स्रोत सूखने से उनके लिए पानी की कमी होती है, जिस कारण जानवरों को पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे शिकार और मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है।

आखिर जब परीक्षा में धांधली हो ही रही तो फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जरूरत क्या है ?

कमलेश पांडे

गृह मंत्रालय को भी परीक्षा में गड़बड़ी की यह सूचना साइबर क्राइम यूनिट से मिली थी। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद ही यह पूरा फैसला लिया गया है। वहीं, मंत्रालय का यह भी कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी मिली थी।



परीक्षा में धांधली कोई नई बात नहीं है, लेकिन आये दिन इसका बदलाव स्वरूप उन मेधावी, मेहनती व गरीब छात्रों के लिए चिंता का सबब बन चुका है जिनका सियासत और प्रशासन में कोई गॉडफादर नहीं होता, जो उन्हें भर बैठे सब कुछ सुलभ करवाता रहे। इसलिए जब भी कोई पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द हो जाती है तो सबसे ज्यादा आर्थिक भार इन्हीं कमजोर छात्रों पर पड़ती है। वहीं सर्वाधिक मानसिक पीड़ा ऐसे ही छात्रों को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से इनके ही सुनहरे सपने प्रभावित होते हैं।

अब देखिए न, नीट-यूजी में गड़बड़ी का मामला अभी निपटा भी नहीं है कि यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली का एक और नया मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद आनन-फानन में शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की पवित्रता बचाने के लिए पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी है। साथ ही बताया गया है कि जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर जब परीक्षा में धांधली हो ही रही है, तो फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन का औचित्य क्या है ?

ख़ास बात यह है कि यूजीसी-नेट की यह परीक्षा एक रोज पूर्व यानी 18 जून को ही देश भर में आयोजित की गई थी। तब परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इसके सफलता पूर्वक संपन्न होने का दावा किया था। हालांकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट को रद्द करने का यह फैसला गृह मंत्रालय से मिले उस इनपुट के आधार पर लिया है, जिसमें पेपर लीक होने समेत बड़े स्तर पर गड़बड़ी की सूचना मिली थी।

बताया जाता है कि गृह मंत्रालय को भी परीक्षा में गड़बड़ी की यह सूचना साइबर क्राइम यूनिट से मिली थी। इसलिए प्राथमिक स्तर पर गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद ही यह पूरा फैसला लिया गया है। वहीं, मंत्रालय का यह भी कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी मिली थी। जबकि गृह मंत्रालय को भी परीक्षा में गड़बड़ी की यह सूचना साइबर क्राइम यूनिट से मिली थी।

उल्लेखनीय है कि यूजीसी-नेट का जिम्मा भी नीट-यूजी परीक्षा आयोजित कराने वाली एनटीए के पास ही था। यूजीसी नेट 18 जून को देशभर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराया गया था, जिसमें 11 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में सुलगाता हुआ सवाल है कि आखिर किस हेराफेरी से बचने के लिए केंद्र में सतारूह मोदी सरकार द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, जब वह जारी ही है तो फिर इसकी जरूरत क्या है ?

क्योंकि नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण पर यदि गौर किया जाए तो प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है कि नेताओं और अधिकारियों का कोई गुप्त गठजोड़ काम कर रहा है, जिनका मकसद प्रतिभाओं का गलाघोंट कर अपने संपर्क में आने वाले छात्रों को मोटी रकम ले-देकर उपकृत करना है। इस प्रकरण में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक निजी सचिव और उसके सम्पर्क में रहने वाले एक सरकारी अभियंता का नाम जिस तरह से उछला है, उससे पूरे प्रकरण की गम्भीरता को समझा जा सकता है।

चाहे बिहार हो या उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश हो या राजस्थान, या फिर इनसे कटकर अलग हुए छोटे-छोटे राज्य, परीक्षाओं में गड़बड़ियां आम बात बन चुकी हैं। वहीं, आंकड़े बताते हैं कि इन परीक्षा धांधली से जुड़े अधिकांश प्रकरणों में जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अमूमन कोई कड़ी नजारी कार्रवाई अबतक नहीं की गई है और न ही उसके लिए कभी कोई कड़ेनिष्ठ कानून बनाया गया है, जिसके चलते ऐसे घाघ लोग प्रायः बच निकलते हैं।

इसलिए यह राष्ट्रीय विमर्श का विषय है कि जिनके उपयोग छात्र जुगाड़ तंत्र के सहारे अच्छे और तकनीकी ओहदे तक पहुंच जाते तो फिर वह क्या करेंगे, अनुमान लगाना कठिन नहीं है। कहीं बहते नवनिर्मित पुल तो कहीं इलाज के दौरान मरता आदमी, इसी बात की तो चुगली करता आया है। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में चले जाएं, आरक्षण से नौकरी पाने वाली जमात की अकर्मण्यता की चर्चा वहां खुलकर देखने-सुनने को मिल जाएगी। उसी तरह से आरक्षण के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित किये जा रहे निजीकरण के नाम पर भी तमाम उलटबांसी करते लोग मिल जाएंगे, जिनकी कर्तूतों से यह संवैधानिक तंत्र कराहने लगा है!

पिछड़ा चला गया। यह ठीक है कि मोदी सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए एक हद तक जदोजहद की, लेकिन फलसफा यह निकला कि महज 10 साल में ही सियासी और संवैधानिक बेड़ियों ने उसे भी जकड़ लिया और लगातार दो बार मिले पूर्ण बहुमत की जगह अब यह सरकार भी अल्पमत में आकर गठबंधन सरकार चलाने के लिए अभिशप्त कर दी गई।

सवाल है कि जब पूरी शिक्षा व्यवस्था काफी महंगी और आम आदमी की पहुंच के बाहर हो चली है, तब शिक्षा पात्रता परीक्षा में धांधली और पक्षपात के बीच आम आदमी के घर से निकला प्रतिभाशाली छात्र आखिर किधर जाएगा यदि ऐसा सुनियोजित भ्रष्टाचार आम छात्रों को कतिपय महत्वपूर्ण अवसरों से दूर कर देता तो फिर वो आगे क्या करेंगे, अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसी तरह से सरकारी नौकरियों की प्राप्ति में हो रही धांधली और निजी क्षेत्र में नौकरी की उटपटांग व्यवस्था से सेवा शर्तों के बीच पीस रहे आम नीमिहालों के भविष्य के बारे में यदि हम-आप नहीं सोचेंगे, तो सोचगा कौन ? यक्ष प्रश्न है।

इसलिए सरकार और प्रशासन का यह दायित्व है कि वह शिक्षा प्राप्ति से लेकर नौकरी प्राप्ति तक, या फिर कौरोबारी दरवाजे खुलने तक पूरे देश में एक समान शिक्षा व परीक्षा प्रणाली लागू करे, जो पारदर्शी और भेदभाव रहित हो।

इसकी सफलता से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी, बल्कि देश भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर मजबूत होगा। वहीं, शिक्षा, शैक्षणिक पात्रता परीक्षा व नौकरी पात्रता परीक्षा को केंद्रीकृत किये जाने के बजाय उन्हें विकेंद्रीकृत किया जाए, ताकि पूरे देश के लोग समान रूप से उससे लाभान्वित हो सकें।

टाईम पास

काकुरो पहेली - 3220. A crossword puzzle grid with some numbers filled in.

हंसी के फूटवारे. A word search puzzle with a grid and a list of words to find.

फिल्म वर्ग पहेली - 3220. A grid puzzle where numbers correspond to movie titles.

ऊपर से नीचे. A grid puzzle with a list of words to be placed in the grid.

काकुरो - 3219 का हल. The solution to the 3219 Kakuro puzzle.

हंसी के फूटवारे का हल. The solution to the word search puzzle.

फिल्म वर्ग पहेली - 3220 का हल. The solution to the movie grid puzzle.

ऊपर से नीचे का हल. The solution to the word placement puzzle.

सूडोकु - 3220 का हल. The solution to the 3220 Sudoku puzzle.

शब्द पहेली - 3220 का हल. The solution to the word puzzle.

वाएँ से दाएँ. A word search puzzle with a list of words to find.

ऊपर से नीचे. A grid puzzle with a list of words to be placed in the grid.

वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाने में हो रही लेटलतीफी

वन विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट लटका, जेवर एयरपोर्ट के पास होगा निर्माण

गौतम बुद्ध नगर। जीवों को संरक्षित करने के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही इसको बनाने की तैयारी शुरू हो गई। जिसको वन विभाग और यमुना प्राधिकरण मिलकर बनाएंगे।

इसको लेकर यमुना प्राधिकरण जमीन भी उपलब्ध करा चुका है और बजट भी दे चुका है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस मामले में देर हो रही है।

वहीं एयरपोर्ट बनाने वाली ज्यूरिक कंपनी जल्द से जल्द एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाने की मांग कर रही है।

यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर में जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। उसके आसपास वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र बनाया है। इसको लेकर



डब्ल्यूईई ने एक स्टडी की थी। उसी स्टडी पर एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाने की योजना बनी, क्योंकि यहां पर ब्लैक बॉक्स, सारस भी हैं। इन सभी को संरक्षित करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो यह विलुप्त भी हो सकते हैं।

अगर कभी गलती से ये एयरपोर्ट की बाउंड्री में या रनवे के आसपास आ जाए तो तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए एयरपोर्ट के पास रेस्क्यू सेंटर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर 10 हेक्टेयर जमीन की

जाया है। ज्यूरिक कंपनी के द्वारा बार-बार यमुना प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी जा रही है और कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट बनने जा रहा है लेकिन अभी तक एनिमल रेस्क्यू सेंटर नहीं बनाया गया है।

इसकी वजह से एयरपोर्ट के संचालन में मुश्किल आ सकती और परेशानी होगी।

इस मामले में डीएफओ को भी कई बार कहा गया है लेकिन उनका कहना है कि वह यह प्रस्ताव शासन को भेज चुके हैं लेकिन शासन के स्तर पर मामले में देरी हो रही है।

यमुना प्राधिकरण के द्वारा 5 करोड़ से ज्यादा रुपया भी वन विभाग को दे दिया गया। वहीं धनोरी वेतलैंड में साफ सफाई के लिए भी पैसा दिया गया।

अरुणवीर सिंह ने बताया कि जमीन और पैसा देने के बाद भी अभी तक वहां पर कोई कार्य शुरू नहीं हो

पाया है। ज्यूरिक कंपनी के द्वारा बार-बार यमुना प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी जा रही है और कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट बनने जा रहा है लेकिन अभी तक एनिमल रेस्क्यू सेंटर नहीं बनाया गया है।

इसकी वजह से एयरपोर्ट के संचालन में मुश्किल आ सकती और परेशानी होगी।

इस मामले में डीएफओ को भी कई बार कहा गया है लेकिन उनका कहना है कि वह यह प्रस्ताव शासन को भेज चुके हैं लेकिन शासन के स्तर पर मामले में देरी हो रही है।

यमुना प्राधिकरण के द्वारा 5 करोड़ से ज्यादा रुपया भी वन विभाग को दे दिया गया। वहीं धनोरी वेतलैंड में साफ सफाई के लिए भी पैसा दिया गया।

अरुणवीर सिंह ने बताया कि जमीन और पैसा देने के बाद भी अभी तक वहां पर कोई कार्य शुरू नहीं हो

10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शहरभर में हुआ योगाध्यास



नोएडा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शुकुवार को विभिन्न स्कूल - कॉलेज और संस्थानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

जिसमें सेक्टर-62 स्थित एनआईओएस में योग दिवस के मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। इसमें संस्था के योग शिक्षक रने विभिन्न योग आसन कराकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।

योग कार्यक्रम का प्रसारण देश भर में एनआईओएस के मीडिया स्टूडियो ई-विद्या टीवी चैनल और यू-ट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया गया। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों में 22 क्षेत्रीय केंद्रों को भी जोड़ा गया। इस मौके पर नोएडा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रो. सरोज शर्मा ने योग दिवस को मन, चित और शरीरा को समाज एवं ब्रह्मांड से जोड़ने का दिन बताया। इसी के साथ डीएवी

पब्लिक स्कूल में शुकुवार को योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने योग शिक्षक संदीप के मार्ग दर्शन में सुकम प्राणायाम, पवन मुक्त, वृक्षासन, उतानपाद आसनों को किया। कार्यक्रम में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से भी भाग लिया तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया।

विद्यालय की प्रधानाचार्य चित्राकांत ने छात्रों को योग दिवस मनाने के कारण बताते हुए इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह दी। गर्मियों की छुट्टियों के मौके पर शुकुवार को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चकर माध्यमिक स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों-शिक्षक और अभिभावकों को स्कूल में योग कराया गया। इसमें लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने आदेश जारी किया गया था।

शार्ट न्यूज

बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल के कारावास की सजा

ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की ओर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो) की कोर्ट ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का रिश्ते में मामा लगता है। घर पर बच्ची अकेली थी, तभी आरोपी ने अंजाम दिया। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी ने बताया कि वर्ष 2017 में पीड़ित बच्ची के पिता ने सेक्टर-49 कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि चार अक्टूबर को उनकी बेटी घर पर अकेली थी। बच्ची को मां बाजार गई थी। तभी वहां पर बांदा के सुहाना निवासी प्रेमदीप पहुंचा। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तभी एक महिला घर पर पहुंच गई और बच्ची को बचा लिया। आरोपी बच्ची का मामा लगता है।

रवि काना की पुलिस ने मांगी रिमांड

ग्रेटर नोएडा। स्कूप माफिया रवि काना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने के लिए पुलिस ने अदालत से अनुमति मांगी है। इस रिमांड पर अदालत में 26 जून को सुनवाई होगी है। माफिया रवि काना से पूछताछ कर उसके गैंग, मददगारों और काले धंधे में लिस लोगों तक पुलिस पहुंचना चाहती है। जेल में बंद रवि काना वाले मामले में कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह लोड ट्रक को जल करवाया है। जब की गई संपत्ति अनुपयोगी अवस्था में थे। इस मामले में पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी रिमांड मांग रही है। अगर अदालत में यह अर्जी स्वीकार होती है तो पुलिस को उसकी रिमांड मिलेगी और पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उससे पूछताछ कर सकेगी। स्थानीय स्तर पर स्कूप माफिया की सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

नगर निगम टीम और व्यापारियों में टकराव

गाजियाबाद। गाजियाबाद की मार्केट में शुकुवार को पॉलिथीन ज्वल करने पहुंची नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम और व्यापारियों में झड़प हो गई। इस दौरान किसी ने पत्थर मार दिया, इस हमले में प्रवर्तन दल में शामिल सुरक्षाकर्मी का सिर फूट गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने व्यापारियों पर लाठियां फटकार दी। इससे अक्रोशित सैकड़ों अपनी अपनी दुकानें बंद करके थाने पर पहुंच गए हैं। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है। सिहानी गेट क्षेत्र की सब्जी मंडी में दुकान चलाने वाले विकास ने बताया, शुकुवार को नगर निगम का प्रवर्तन दल मार्केट में आया। मेरी दुकान से उन्होंने करीब तीन किलो पॉलिथीन ज्वल की। फिर मुझसे 25 हजार रुपए मांगे। 10 हजार रुपए में मामला सेटलमेंट हो गया। फिर भी हमारी चालान की रसीद काट दी। हमने विरोध किया तो उन्होंने पापा को लाठियां मारी। इस घटना के बाद वहां तमाम व्यापारी इकट्ठा हो गए। आरोप लगाया कि नगर निगम की टीम इस अभियान की आड़ में पैसा वसूल रही है और व्यापारियों से अभद्रता कर रही है। नोकझोंक के बीच ही किसी ने नगर निगम की टीम पर पत्थर बरसा दिए। एक पत्थर प्रवर्तन दल के सुरक्षाकर्मी को लगा और उसके सिर से खून बहने लगा।

बाबा साहेब पर टिप्पणी, एफआईआर

गाजियाबाद। गाजियाबाद में वॉट्सएप ग्रुप में एक शख्स ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पार्षद ने इस मामले में थाना विजयनगर में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम सेल से भी जांच कराई जा रही है। विजयनगर वार्ड-3 के पार्षद भावत स्वप्न उर्फ भारत गौतम ने बताया कि लक्ष्य ट्रेडिंग कंपनी नाम से एक वॉट्सएप ग्रुप बना है। इसमें टीके चौहान नामक व्यक्ति ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अशुभ चित्र खलना करने का प्रयास किया है। पार्षद ने कहा कि इससे बाबा साहेब के अनुयायी और देशभर के सम्मानित नागरिकों में आक्रोश है। धीरे-धीरे ये फोटो अन्य कई ग्रुप में वायरल हो गया। जिसके बाद लोगों ने आपत्ति दर्ज करानी शुरू कर दी। इस मामले में शुकुवार को पार्षद भावत स्वप्न उर्फ भारत गौतम ने थाना विजयनगर में पहुंचे और टीके चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस से कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तहरीर के आधार पर आरोपी टीके चौहान के खिलाफ धारा 505 507 और 87ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

आईपीओ और शेयर बाजार में निवेश का झंसा देकर सात लाख टगे

नोएडा। साइबर अपराधियों ने घर बैठे ऑनलाइन नौकरी करके लाखों कमाने का झंसा देकर ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक युवक के साथ सात लाख रुपये की ठगी कर ली है। जालसाजों ने पीड़ित को वॉट्सएप ग्रुप में जोड़कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इसको लेकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई शिकायत में विकास शर्मा ने बताया कि उनके पास कुछ समय पहले वॉट्सएप पर मेसेज आया, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग करके लाखों रुपये कमाने की बात कही गई थी। उन्होंने जब उक्त वॉट्सएप नंबर पर बात की तो उनको रुपय में जोड़ दिया गया। इसके बाद उनको कुछ टास्क दे दिए गए, जिसको उन्होंने पूरा कर दिया। इस दौरान उनको कुछ फायदा हुआ। इसके बाद आरोपियों ने अगले टास्क में ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए कहा। विकास ने बताया कि जालसाजों के झंसे में आकर उन्होंने कई नामी कंपनियों के शेयर और आईपीओ में निवेश किया। शेयर बाजार को लेकर उनको जालसाज ऑनलाइन लेक्चर भी देते थे। वे कंपनी के बारे में और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी देते थे। उन्होंने जिन कंपनियों में निवेश किया था, जालसाजों ने उनके दस्तावेज भी उपलब्ध कराए।

काम के बहाने बुलाकर किशोरी से दुष्कर्म

नोएडा। फेज तीन थाना क्षेत्र स्थित गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। गंवती होने पर किशोरी की मां को इसकी जानकारी हुई। किशोरी की मां ने आरोपी को नामजद करते हुए फेज तीन थाने में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। किशोरी की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह आरोपी साहिल कुमार के यहां काम करने जाती थी। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो साहिल ने बेटी को काम पर भेजने को कहा। साहिल के कहने पर उन्होंने अपनी बेटी को काम करने के लिए भेजना शुरू किया। इसी बीच आरोपी साहिल ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी किशोरी को धमकाकर लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने घर पर किसी को इस बारे में बताने पर किशोरी को जतन से मारने की धमकी भी दी थी। जब किशोरी तीन माह की गर्भवती हो गई तो उसने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। आरोपी की पत्नी एक निजी कंपनी में काम करती है। सभी पहलुओं की ध्यान में रखकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुत्तों के हमले में महिला बुरी तरह घायल

गाजियाबाद जिले में कुत्तों का आवृंक्त धमने का नमन नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडीपी ग्रैंड सवाना सोसाइटी का है, जहां हाउस कीपिंग स्टाफ की एक महिला को 10-12 कुत्तों के झुंड ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के पेट, जांघ, कमर, छाती और प्राइवेट पार्ट तक पर कुत्तों ने बुरी तरह काट दिया। हिंसक कुत्तों ने महिला के गंभीर तथा अन्य हिस्सों से मांस तक बाहर निकाल दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। झुंड़ाजनगर एक्सटेंशन स्थित केडीपी ग्रैंड सवाना सोसाइटी में 35 वर्षीय प्रमिला पिछले 7-8 साल से हाउस कीपिंग का काम करती हैं। शुकुवार की शाम लगभग 4: 30 बजे वह कुत्ता इकट्ठा कर फेंकने गई थीं। कुत्ता फेंककर जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंची अचानक तीन कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ीं। जमीन पर गिरते ही 7-8 कुत्ते और दौड़कर वहां आए और उस पर दूट पड़े।

ग्रेटर नोएडा में 1 घंटे तक फंसी रही लिफ्ट

मां-बेटी हुई परेशान, पंचशील हाईनिश सोसाइटी का मामला

गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पंचशील हाईनीस सोसाइटी में देखने को मिला। जब अचानक से एक लिफ्ट अटक गई। इस लिफ्ट के अंदर मां बेटी फंस गए और करीब 1 घंटे तक वह लोग इसी लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। मेटेनेंस विभाग के लोग लिफ्ट खोलने की कोशिश करते रहे लेकिन वह लिफ्ट को खोल नहीं पाए। जब बाद में एक इंजीनियर को बुलाया गया तो उसने लिफ्ट को खोला।

लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाईनिश सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर रहने वाले मनीषा गुप्ता ने बताया कि गुरुवार रात में उनकी पत्नी सीमा और बेटी अपने

फ्लैट से नीचे लिफ्ट द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे। जैसे ही वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, अचानक से लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट अटक गई। लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद लिफ्ट के अंदर बंद मेरी पत्नी और बेटी काफी घबरा गए। उन्होंने इमरजेंसी बटन को भी दबाया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां पर मौजूद मेटेनेंस विभाग के लोग पहुंचे लेकिन वह लोग भी लिफ्ट को नहीं खोल पाए।

लिफ्ट बंद होने की वजह से उसमें काफी सफोकेशन होने लगा। जिससे कि मेरी पत्नी और बेटी को परेशानी होने लगी। वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा लिफ्ट को लगातार खोलने की कोशिश की जा रही थी लेकिन किसी से भी वह लिफ्ट नहीं खुली।

यूपी रेरा का ग्रेटर नोएडा में बड़ा एक्शन

नामी बिल्डर का दफ्तर सील, 1.50 करोड़ रुपये नहीं देने पर हुआ एक्शन

यूपी रेरा के बकाया को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में सटर तहसील की टीम ने एक प्रमुख बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया। जयदेव बिल्डर पर 1.50 करोड़ रुपये का बकाया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। स्थानीय निवासियों और निवेशकों ने इस कदम का स्वागत किया है, उम्मीद जताते हुए कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुशासन बड़ेगा।

पिछले वर्ष 3277 बिल्डरों के खिलाफ एक्शन

यूपी रेरा ने पिछले वर्ष 3277 बिल्डरों के खिलाफ 1302 करोड़ रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की थी। दिसंबर तक केवल 98.59 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई थी। चुनाव आचार संहिता के कारण कार्रवाई रूकी थी, अब फिर से शुरू हो



गई है। पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में दायरी तहसील में सबसे अधिक बकायेदार बिल्डर है। यह कार्रवाई उन व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिन्हें जिला प्रशासन यूपी रेरा के बकाया की वसूली के लिए कर रहा है।

173 आरसी से 98.59 करोड़ रुपये वसूली

सटर तहसील की टीम ने एक बड़ी

1000 वर्ग मीटर भूखंड आवंटन के फैसले को आयोग ने सही ठहराया

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण के एक हजार वर्ग मीटर का भूखंड महेश मित्रा को आवंटन करने के फैसले को जिला उपभोक्ता आयोग ने सही ठहराया है। आयोग ने मामले को निष्पादन कर दिया है। वहीं, मामले में उच्च न्यायालय के स्टे को बहाल रखा है।

महेश मित्रा बनाम ग्रेनो प्राधिकरण के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में 30 मई 2014 में 500 से 2500 वर्ग मीटर की सीमा के अंदर क्षेत्रफल का प्लाट आवंटित करने

का आदेश दिया था। प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2023 को 1000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित कर दिया। ग्रेनो प्राधिकरण की औपचारिकताएं पूरी करके कब्जा लिया जा सकता है। महेश मित्रा ने आपत्ति दी थी कि प्राधिकरण ने आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। जबकि 2500 वर्ग मीटर के प्लाट के लिए प्राधिकरण को स्वयं सहमति दी थी कि ऑटोमोबाइल कार्यालया लगाने की जरूरत है। प्राधिकरण ने 2500 वर्ग मीटर का प्लाट न देकर केवल 1000 वर्ग मीटर

गाजियाबाद में हिंडन नदी में कूदी युवती

गाजियाबाद में शुकुवार को भाई से नाराज होकर एक युवती हिंडन नदी में कूद गई। एनडीआरएफ की टीम ने हिंडन नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन युवती का अभी कोई पता नहीं चल सका है। इंदिरापुरम सर्किल के एसपी स्वर्णत कुमार सिंह ने बताया- शुकुवार सुबह 11 बजे थाना कोशांबी की सूचना मिली कि वैशाली चौकी क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय पूजा सिंह ने हिंडन नदी की 5/6 की पुलिया पर आकर छलांग लगा दी है। इस सूचना पर पुलिस ने प्राइवेट गोताखोरों को लगाकर जांच शुरू कराई। फलतः नदी मिलने पर पुलिस ने एनडीआरएफ को सूचित किया।

आंधी ने गिराया दिन का पारा, कुछ इलाकों में हुई बूदाबांदी

नोएडा। मानसून की आहत के बीच मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। शुकुवार को दोपहर तक गर्मी बने रहने के बाद करीब तीन बजे मौसम ने घुटन लिया। तेज आंधी के बाद आसमान में बादल छा गए। कुछ जगहों पर बूदाबांदी भी हुई। ऐसे में दोपहर के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग 25 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलने का पूर्वानुमान दे रहा है। शुकुवार को न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री रहा। इसकी वजह से रात के समय गर्मी से मामूली राहत मिली। वहीं, दिन के समय भी आंधी और बूदाबांदी से

अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री बना रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे।

इसके उलट गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार और रविवार को लू चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया। इस बीच अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। 25 जून को दोपहर के बाद बादल छांने के अलावा बूदाबांदी की संभावना बन रही है। वहीं, 26 जून से बारिश शुरू होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग दे रहा है।

निजी गाड़ियों में हूटर मिला तो केस दर्ज होगा

एग्जेंसी
नोएडा। निजी गाड़ियों में हूटर, काली फिल्म, लाल-नीली बत्ती और बदलाव कर नंबर प्लेट में लगाई तो दुकानदार पर एफआईआर दर्ज होगी। यातायात पुलिस ने शुकुवार को सेक्टर-16 कार मार्केट में उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को माइक्र पर घोषणा कर इसकी जानकारी दी गई।
डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव ने कहा कि निजी वाहनों पर काली फिल्म, सायरन-हूटर, लाल और नीली बत्ती लगाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई लोग इसे अपनी गाड़ी में लगवाते हैं।
दुकानदार यदि कार में इसे नहीं लगाएंगे तो वाहन मालिकों के लिए इन्हें लगवाना संभव नहीं है। उन्होंने

कहा कि यदि अभियान के दौरान किसी भी वाहन पर प्रतिबंधित चीजे लगी मिली और वाहन चालक ने जिस दुकान से इसे लगवाया है, इसकी पुष्टि की तो पहले नोटिस और इसके बाद भी नहीं मानने पर दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पहले दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है। डीसीपी यातायात ने कहा कि दुकानदारों को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी में प्रतिबंधित सामान लगाया गया है, उनका नाम और पूरा पता लिखना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों पर यह नियम नहीं लागू है। ऐसे वाहनों के जांच अभियान चलाकर लगातार चालान किए जा रहे हैं।

गाजियाबाद रेप-सुसाइड केस, बिना आईडी प्रूफ कमरा दिया

होटल में इसी बात के ज्यादा पैसे लिए गए, क्राइम स्पॉट सील किया गया

गाजियाबाद। गाजियाबाद में 13 साल की छात्रा ने रेप के बाद सुसाइड कर लिया। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गुरुवार को जेल भेजा। इसमें रेप का आरोपी और होटल मालिक का सगा भाई शामिल है। इन्होंने आरोपी लड़के से ज्यादा पैसे वसूले।

बिना आईडी प्रूफ के कमरा दे दिया। फिलहाल, होटल के उस कमरे को सील कर दिया गया है, जहां वारदात हुई। बाकी विभागों ने भी अब होटल के बारे में जांच शुरू कर दी है।
कस्बा मोदीनगर में रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा को दोस्ती कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर मोदीनगर के ही हिमांशु सोनी नामक लड़के से हुई थी। हिमांशु ने मंगलवार शाम छात्र को मिलने के बहाने बुलाया और उसे तहसील के सामने एक होटल पर ले गया।
आरोप है कि होटल के कमरे में हिमांशु ने छात्रा से जबरन रेप किया।



छात्र ने विरोध किया तो आरोपी ने पिटाई कर दी। इसके बाद वह जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। अगले दिन यानि बुधवार को पीड़िता ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी।

आरोपी और होटल मालिक भाई जेल भेजे

गुरुवार को पुलिस ने मामले के

निपट गया था। आरोपी का सैलून भी है। आरोपी का भी इसी तरह का कुछ विवाद पूर्व में हुआ था।

होटल मालिकों का पिता एसडीएम कोर्ट में है तेनात

दोनों आरोपियों के पिता एसडीएम कोर्ट में काम करते हैं, इसलिए पुलिस आज तक इस होटल पर कोई एक्शन नहीं ले पाई।

जबकि इस होटल में अनैतिक काम होने की शिकायतें कई बार पुलिस मिलती रही हैं। लेकिन अब इस होटल पर पेश होने और पोलिटा के सुसाइड करने की घटना के बाद पूरा पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। अग्निशमन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों ने जांच शुरू कर दी है कि इस होटल पर सभी एनओसी हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस होटल पर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

अमेरिका ने रूसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को बैन करने की घोषणा की



वाशिंगटन। अमेरिका ने साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर्सकी द्वारा बनाए गए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा कि रूसी सरकार की आक्रामक साइबर क्षमताओं और कैस्पर्सकी के संचालन को प्रभावित करने या निर्देशित करने की क्षमता के कारण अमेरिका में कंपनी के संचालन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। कैस्पर्सकी अब आम तौर पर अन्य गतिविधियों के अलावा अमेरिका में अपने सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकेगी और न ही पहले से उपयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयर के अपडेट प्रदान करने में सक्षम होगी। वाणिज्य सचिव जीना रायमांडो ने कहा, रूस ने बार-बार दिखाया है कि उनके पास कैस्पर्सकी लैब जैसी रूसी कंपनियों का शोषण करने की क्षमता और इरादा है, ताकि वे सवेदनशील अमेरिकी जानकारी एकत्र कर सकें और हथियार बना सकें। हम अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर उपकरण का उपयोग करना जारी रखने वाले हैं। अमेरिका में कैस्पर्सकी सॉफ्टवेयर की बिक्री पर 20 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रूसी बहुराष्ट्रीय कंपनी 29 सितंबर तक मौजूदा यूजरों को सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करने में सक्षम होगी। कैस्पर्सकी का सॉफ्टवेयर यूजरों को ट्रोजन, स्पाइवेयर और अन्य साइबर खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

खालिस्तानी आतंकवादियों ने लगाई नागरिक अदालत, भारत ने जताई आपत्ति

टोरंटो। भारत ने वैक्यूम में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा नागरिक अदालत लगाने और भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जलाने पर कनाडा सरकार के सामने कड़ा विरोध जताया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने कनाडा के उच्चायोग को राजनयिक नोट जारी कर खालिस्तानी आतंकवादियों की हालिया कार्रवाइयों और नागरिक अदालत आयोजित करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। नोट में भारत ने कनाडाई उच्चायोग को जस्टिन ट्रुडो सरकार द्वारा कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को दी जा रही शह की कड़ी निंदा की है। कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की याद में मौन रखा गया था, जिसके एक दिन बाद भारत ने यह आपत्ति जताई है। निज्जर की पिछले साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गोली मारकर हत्या दी गई थी।

तलाक के लिए आईफोन को बताया दोषी, टोका मुकदमा, पत्नी ने पकड़ लिया था रंगे-हाथों

लंदन। इंग्लैंड के अज्ञात व्यक्ति ने पत्नी से तलाक के लिए आईफोन को जिम्मेदार ठहराते हुए एप्पल कंपनी पर मुकदमा टोक दिया है। युवक का दावा है कि उसकी पत्नी को सेक्स वर्कर्स के साथ उसकी संबंधों का पता उनके साझा आईफोन के जरिए चला, जहां उसके आईमैसेज उसके आईफोन से डिलीट होने के बावजूद बने रहे। यही वजह है कि शाख्स ने 6.3 मिलियन डॉलर का मुकदमा किया है। शाख्स को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एप्पल का सिक फौचर एक ही एप्पल आईडी वाले डिवाइसों पर मैसेज को सुरक्षित रखता है। ऐसे जब उनकी पत्नी को यह सबूत मिला और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दायर कर दिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अनजान शाख्स ने लंदन बेस्ड लीगल फर्म रॉसेनब्लाट के जरिए आईफोन मेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। मुकदमा इस तर्क पर केंद्रित है कि आईमैसेज के फवर्शन में अलग-अलग डिवाइस पर मैसेज को हटाने के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। शाख्स का मानना है कि अगर यह खुलासा इस तरह से नहीं होता, तो शायद शादी को बचाने का एक मौका होता। शाख्स का तर्क है कि उनकी पत्नी को इस बारे में काफी गलत तरीके से पता चला। उनके मुताबिक अगर वे अपनी पत्नी से तर्कसंगत तरीके से बात कर पाते और तो उन्हें इस बात का शायद इतना गलत अहसास नहीं होता और वे शायद शादीशुदा होते शाख्स ने कहा कि यदि आपको बताया जाता है कि कोई मैसेज हटा दिया गया है तो आपको ये मानने का अधिकार है कि वह हटा दिया गया है। शाख्स ने कहा कि अगर मैसेज में ये लिखा होता कि इन मैसेज को केवल इस डिवाइस से डिलीट कर दिया गया है। तब भी आपके पास समझने का एक हिंट होता। उन्होंने आगे कहा कि मैसेज केवल इस डिवाइस में डिलीट किए गए हैं। ऐसा कहना ज्यादा साफ तौर पर इंडिकेट करता। अब वह एप्पल को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामूहिक मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे हैं, जिन्होंने तकनीकी गलतफहमी के कारण इसी तरह की स्थितियों का सामना किया है। तब अन्य पुरुषों के लिए सामूहिक मुकदमा दायर करना चाहते हैं, जो अपने फोन का इस्तेमाल करना नहीं जानते।

पुतिन ने तानाशाह को तोहफे में दी कार...

मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे तब अपने मित्र और तानाशाह किम जोंग उन को ऐसा तोहफा दिया, जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैल गई। पुतिन ने लिमोजिन कार तानाशाह किम जोंग को तोहफे में दी है। इस कार को रॉयल्स रॉयल्स की कंपनी कहा जा रहा है, लेकिन कार की खासियत दुनियाभर की गाड़ियां इसके आगे पानी भरती हैं। न सिर्फ कीमत बल्कि फीचर्स भी कार को पूरा बंदर बना देते हैं।

दरअसल, ऑरस लिमोजिन कार को खासतौर पर पुतिन के लिए ही बनाया गया है। जाहिर है कि इसकी खूबियां भी जबदस्त होंगी। इस कार को पुतिन के खास निदेश पर बनाया गया है और पहली बार साल 2018 में उतारी गई। इसका डिजाइन रूस की कंपनी नामी ने तैयार किया है, जबकि मॉडल को रूस की सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। ऑरस कंपनी की इस सीनेट ब्रांड के 3 मॉडल आते हैं। इसमें स्टैंडर्ड सीनेट, सीनेट लांग और सीनेट लिमोजिन शामिल है। रूसी कंपनियों का कहना है कि यह 1940 में सोवियत काल के समय बनी जेडआईएस 110 सोवियत लिमोजिन से प्रेरित है। किम जोंग उन के पास पहले से ही मर्सिडीज के चार मॉडल और एक लेक्सस कार है। अब उनके बेड़े में रूस की यह सुपर कार भी शामिल हो गई है।

यह कार 6,700 मिमी (6.70 मीटर) लंबी है और इसका वजन 2,700 किलोग्राम है। कार को पूरी तरह बुलेट प्रूफ बनाया गया है और इस पर गोलियों या बम का जरा भी असर नहीं होता। चाहे गाड़ी पर बम फेंका जाए या जमीन में रखकर विस्फोट किया जाए, यह कार नीचे से ऊपर तक पूरी तरह सुरक्षित है। कार में सेल्फ कंटेन ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, जबकि टायर फ्लैट रबर से बने हैं। कार के अंदर ही सिवयोर लाइव कम्प्यूटेशन सिस्टम है, जो दुनिया में कहीं भी बात करने की सुविधा देता है। इतना ही नहीं यह कार खुद भी कई तरह के ताकत हथियारों से लैस है। ये फीचर कार को एक बंकर में तैयार कर देते हैं।

ऑरस लिमोजिन में 6.6 लीटर वी 12 इंजन लगा है। यह 850 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। इसका इंजन बनाने में पोर्श ने भी मदद की है। भारत में बिकने वाली ल्पजरी एसयूवी फोर्च्यूनर के मुकाबले इसमें 4 गुना से भी ज्यादा ताकत है। फोर्च्यूनर 201 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। जाहिर है कि यह ऐसी 4-4 कारों को एकसाथ खींच सकता है। सबसे पहले इसे साल 2018 में उतारा गया था, तब इसकी कीमत 1.6 लाख डॉलर (1.32 करोड़ रुपये) थी। साल 2021 में इसकी कीमत रिवाइज करके 3 लाख डॉलर (2.40 करोड़ रुपये) कर दी गई। रूसी एजेंसियों के मुताबिक, 2024 में अब तक रूस में इसके 40 मॉडल की बिक्री हुई है। साल 2022 में सिर्फ 31 कारों की ही बिक्री हुई थी।



बांग्लादेश में आई बाढ़ के बीच ही पानी में डूबा नजर आ रहा सियालहाट इलाका।

सांसद चंद्रा आर्य ने खालिस्तान समर्थकों को कनाडा की संसद में सुनाई खरी-खरी

ओटावा (एजेंसी)। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने संसद में खड़े होकर खालिस्तान समर्थकों को जमकर कोसा। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि 23 जून को भारतीय विमान को हवा में उड़ान दिया गया था। इसके जिम्मेदार कनाडाई खालिस्तानी आतंकी थी। चंद्रा आर्य ने एक्स पर लोगों से 1985 एयर इंडिया बम विस्फोट के पीछियों की याद में एक समारोह में शामिल होने की अपील की। विमान पर हमले की यह 39वीं बरसी है। इसे आतंकवाद के पीछियों के लिए राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रा आर्य ने कहा कि यह कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक हत्या है। इसके बाद उन्होंने हाल ही में खालिस्तान समर्थकों की



ओर से भारतीय पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, कनाडा की संसद में हाल ही में खालिस्तान समर्थकों की ओर से हिंदू भारतीय पीएम की हत्या का जश्न मनाया गया, जिसमें हिंसा और नफरत का महिमामंडन किया गया, जो दिखाता

है कि अंधेरी ताकतें फिर सक्रिय हो गई हैं। ये दिखाता है कि देश के लिए आने वाला समय भयानक होगा। 23 जून 2024 को इस मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने लोगों को आने को कहा। यह आयोजन राजधानी ओटावा में डॉब

झील के पास और ऑटोरियो में क्रॉस पार्क साउथ लॉन में स्मारक स्थल पर 12 बजे आयोजित की जाएगी। संसद में उन्होंने खालिस्तान समर्थकों की ओर से हिंसा को बढ़ावा देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 23 जून आतंकवाद के पीछियों के लिए स्मृति दिवस है। 39 साल पहले इसी दिन एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से लगाए गए बम से हवा में ही उड़ गई थी। उन्होंने आगे याद दिलाते हुए कहा कि विमान में सवार सभी 329 यात्री और चालक दल की मौत हो गई थी। कनाडा के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इस हमले में 268 कनाडाई लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक थे।

आतंकवाद से निपटने के लिए अभियोजन तंत्र को मजबूत बनाएं: राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी

इस्लामाबाद। (एजेंसी)। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आतंकवाद और अज्वाद से उदय खतरे का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने एवं उनके अभियोजन तंत्र में सुधार लाने का आह्वान किया है। समाचार पत्र 'खब' की एक खबर के अनुसार, जरदारी ने अशांत प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिए गए अधिकार में खामियों के बारे में भी बताया गया। इरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे बलूचिस्तान में लंबे समय से अज्वाद है और वहां अक्सर सैन्य कार्रवाइयों एवं सुरक्षा कर्मियों पर हमले होते रहते हैं। बंदरगाह शहर खादर में हुई बैकड में जरदारी ने प्रांतीय सरकार के प्रयासों के साथ-साथ

आतंकवाद से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बलिदान की सरहना की, लेकिन उन्होंने सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खबर में उनके हवाले से कहा गया है, अभियोजन तंत्र में सुधार की आवश्यकता है, ताकि आतंकवादी न्याय की जद से नहीं बच सकें। भारत में सक्षम और बहादुर पुलिस अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे प्रांत में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। एकसंघ टिप्पण समाचार पत्र की एक अन्य खबर के अनुसार, जरदारी ने राजनीतिक संवाद पर जोर देते हुए कहा कि बलूचिस्तान में समृद्धि, विकास और शांति लाने के लिए यही रास्ता है। राष्ट्रपति को बताया गया कि प्रांतीय सरकार चीनी और विदेशी नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कदम उठ रही है।

इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सैकड़ों लोगों ने किया योग



- भारतीय राजदूत सिंगला बोले- योग केवल शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास नहीं

तेल अवीव (एजेंसी)। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर इजराइल में तीन सौ से ज्यादा लोगों ने पेरस सेंटर फॉर पीस एंड इनेवेशन में योग किया और इसे अपने जीवन में हमेशा करने का संकल्प लिया। इस योग कार्यक्रम में प्रथम महिला मिशाल हेजोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं और उन्होंने भी योग किया।

इस मौके पर इजराइल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इजराइल में भारतीय दूतावास ने तेल अवीव-याफो नगर पालिका और इजराइल के संस्कृति और खेल मंत्रालय के सहयोग से योग दिवस का आयोजन किया था। इस मौके पर हेजोग ने भारत और

इजराइल के बीच गहरी दोस्ती पर बात की। हेजोग ने कहा कि आपने आज स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि भारत परवर्ध करता है। भारत, इजराइल के साथ हमेशा खड़ा है। युद्ध के शुरूआती क्षणों में ही दोस्ती की यह भावना स्पष्ट दिखी। हेजोग ने कहा कि भारत के पीएम नरेन्द्र मोदी ने आगे आकर नरसंहार की निंदा की थी और हमारे बंधुओं की रिहा करने की मांग की थी। इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने कहा कि योग की प्राचीन क्रिया ने सीमाओं और संस्कृतियों को पार किया है। उन्होंने कहा कि हम इस कालातीत परंपरा के सार पर विचार करें। योग की मूल शिक्षा केवल शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास नहीं बल्कि इसे करने से एकता, करुणा और मन को शांति भी मिलती है। योग सत्र की शुरुआत दूतावास की योग शिक्षिका दर्शना राजपूत के नेतृत्व में योग मुद्राओं की प्रस्तुति से हुई।

भारतीय छात्रों को ... अमेरिका में ट्रंप की गारंटी

वाशिंगटन (एजेंसी)। आब्रजन के मुद्दे पर अपने सख्त रुख में आश्चर्यजनक बदलाव कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कॉलेजों से ग्रेजुएशन करने वाले विदेशी छात्रों को सीधे ग्रीन कार्ड देने की इच्छा जाहिर की है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि 'मैं जो करना चाहता हूँ और जो करूँगा, वह यह है कि जब आप किसी कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, तब मुझे लगता है कि आपको अपने डिप्लोमा के हिस्से के रूप में खुद-ब-खुद ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, इस देश में रहने में सक्षम होने के लिए एक ग्रीन कार्ड। उन्होंने प्रस्ताव में दो साल के जूनियर कॉलेजों और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के ग्रेजुएट को भी शामिल करने के लिए कहा।



ट्रंप का यह बदला हुआ मिजाज अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का जोश बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 शैक्षणिक वर्ष के दौरान अमेरिका में उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने वाले भारतीय छात्रों की संख्या अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। यह उछाल पिछले साल की तुलना में 3.5 फीसदी बढ़ोतरी की दिखाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि 200,000

से अधिक भारतीय छात्रों ने विभिन्न अमेरिकी संस्थानों में दाखिला लिया, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने के मौके ने अमेरिका को भारतीय छात्रों के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया है। ट्रंप की यह ताजा टिप्पणी उनके विशिष्ट आप्रवासी विरोधी बयानबाजी

को छोड़ने का संकेत देती है। ट्रंप अक्सर आप्रवासियों को सार्वजनिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा और सरकारी संसाधनों के लिए खतरा बताते रहे हैं। जब तुनिया भर से सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों को अमेरिका में लाने की योजना के बारे में पूछा गया, तब ट्रंप ने जवाब दिया 'मैं इसका वादा करता हूँ। गौरतलब है कि ग्रीन कार्ड या स्थायी निवासी कार्ड, अमेरिकी नागरिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रंप की योजना का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अमेरिका में बनाए रखना है जिन्होंने अमेरिका में अपनी शिक्षा हासिल की है जो अक्सर इन छात्रों को उनके गृह देशों में वापस लौटते हुए देखते हैं।

इसरो के अंतरिक्षयात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी, रहने का मिलेगा प्रशिक्षण

वाशिंगटन (एजेंसी)। इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी चल रही है। वहां रहने और खुद को सखाइय करने की ट्रेनिंग देकर उन्हें यात्रा पर भेजा जाएगा। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के भी एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहने की ट्रेनिंग देगी। क्रिटिकल और आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि इसे करने से एकता, करुणा और मन को शांति भी मिलती है। योग सत्र की शुरुआत दूतावास की योग शिक्षिका दर्शना राजपूत के नेतृत्व में योग मुद्राओं की प्रस्तुति से हुई।

एक अंतरिक्षयात्री को आईएसएस तक जाने, वहां रहने और लौटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसे भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बातें कही हैं। बिल नेल्सन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्री के साथ संयुक्त अभियान करेगा। बता दें कि दोनों एनएसएस ने अंतरिक्ष उड़ान सहयोग और रणनीतिक ढांचे के विकास के लिए बातचीत की। यह नासा और इसरो अंतरिक्षयात्रियों का पहला संयुक्त प्रयास होगा। संभव है कि इस साल के अखिरी में भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएसएस के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम मिलकर काम करेंगे और इसरो के

अंतरिक्षयात्रियों का चुनाव करे। नासा और इसरो साथ नासा इसरो सिंक्रोनिक अपचरं रखर यानी निसार को लॉन्च करने जा रहे हैं। यह मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोगी हो सकता है। यह हर 12 दिन में दो बार पृथ्वी की मैपिंग करेगा। जेक सुलिवन और एनएसएस अजीत खेभाल बीच बातचीत के बाद यह ऐलान किया गया है। इस उग्रवह को नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। बता दें कि भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित खेभाल और उनके समकक्ष जेक सुलिवन के बीच हुई मुलाकात के बाद नेल्सन ने यह बात कही है। सुलिवन ने सोमवार को कहा था कि इसरो के अंतरिक्षयात्रियों को अडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी।

बलूचिस्तान में लगातार हो रहा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जबरन गायब किए गए लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग

इस्लामाबाद। (एजेंसी)। बलूचिस्तान के तुर्बत में फिदा चौक से सैकड़ों प्रदर्शनकारी जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और जबरन गायब किए गए लोगों की सुरक्षित रिहाई की मांग की। बलूच यकजहती समिति (BYC) ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया है। शुरूआत को यह विरोध प्रदर्शन लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। 'तेज गमी' में चार दिनों तक धरना देने के बाद, परिवार अथ व्रत कार्यालय की ओर मार्च कर रहे हैं, जहाँ वे अपने प्रियजनों के वापस आने तक अपना

विरोध जारी रखेंगे। इस कठिन समय में, हम अपने देश से D.C. कार्यालय के सामने धरने में भाग लेने और अपने बुजुर्ग पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि उनके दुख और तकलीफें शब्दों से परे हैं। BYC ने X पर पोस्ट किया। BYC ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन, उन्होंने पुष्टि की कि जबरन गायब किए गए पीड़ितों को वापस लाने के लिए प्रदर्शनकारियों का दृढ़ संकल्प 'दृढ़' बना

हुआ है। बाद की पोस्ट में कहा गया अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी के लिए परिवारों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। इस भीषण गर्मी में वे अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन छुट्टी पर होने का दिखावा कर रहा है। वे धरना प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं और इन बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों की बात भी नहीं सुन पा रहे हैं, जो बेहद निराशाजनक है। हम केच के लोगों से इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने और अपने बुजुर्गों का समर्थन करने की अपील करते हैं, क्योंकि हम ही

उन्की एकमात्र उम्मीद है। इससे पहले, बीवाईसी ने घोषणा की थी कि तुर्बत के शहीद फिदा चौक पर चल रहा धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक जबरन गायब किए गए लोगों को सुरक्षित रिहा नहीं कर दिया जाता। बीवाईसी ने आगे कहा कि गायब हुए लोगों की सुरक्षित वापसी के बारे में स्थानीय प्रशासन के वादों के बावजूद, मौजूदा अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीवाईसी ने कहा, 'ईद आ गई और चली गई, लेकिन बलूच परिवार ईद के बाद से लापता अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग करते हुए शहीद फिदा



चौक तुर्बत पर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जिला प्रशासन ने पहले उन्हें उनके प्रियजनों की रिहाई का झूठ आश्वासन दिया था। अब, कोई भी राज्य प्रधिकरण उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आया है।' बलूच यकजहती समिति ने

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने का आह्वान किया और उन सभी बलूच व्यक्तियों की रिहाई की मांग की जिन्हें जबरन गायब कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करने की तैयारी में चुनाव आयोग, जमीनी स्तर पर शुरु किया काम

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक भागीदारी ने भारतीय चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अद्यतन करने के साथ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। पिछली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जब यह अभी भी एक राज्य था और अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में, राज्य का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया और दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तब से यूटी विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा तय की है। बताया जा रहा है, चुनाव आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश में जमीनी काम शुरू कर दिया है और विधानसभा चुनाव कराने के लिए अगस्त और सितंबर के बीच की अवधि पर विचार हो रहा है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों के लिए अस्थायी समयसीमा की घोषणा नहीं की है। शुक्रवार को जारी बयान में, चुनाव निकाय ने कहा कि लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और इन राज्यों में मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 को अर्द्धांत तिथि के रूप में निष्पादित की गई है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक नए सदन के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के लिए आम चुनाव भी आयोजित किया जाना है।

पुणे कार दुर्घटना मामला : सुनवाई पूरी... फ़ैसला 25 जून को

मुंबई। पुणे कार दुर्घटना मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग आरोपी की चाची द्वारा उसकी गिरफ्तार के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। 17 वर्षीय आरोपी पिछले माह कल्याणी नगर में हुई एक सड़क दुर्घटना में कथित रूप से शामिल था, जिसमें दो युवा तकनीशियन मारे गए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट 25 जून को अपना फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई कर हाईकोर्ट ने कहा, पीड़ितों के परिवार सदमे में है। लेकिन शराब के नशे में दुर्घटना करने वाला किशोर भी सदमे में है। स्वाभाविक रूप से, इसका उसके दिमाग पर असर पड़ा होगा। इसके पहले 19 जून को पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आरोपी के खिलाफ सभी सबूतों का विवरण दिया था। पुलिस ने मामले में सुनवाई के लिए किशोर को वयस्क के रूप में मानने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा, हमने जेजेबी को सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो साबित करते हैं कि वह 19 मई की शाम को अपने घर से शुरु होकर दुर्घटना होने तक पोशं कार चला रहा था। रिपोर्ट में उन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल हैं, जिन्होंने नाबालिग को कार चलाते हुए देखा, जांच के दौरान बरामद सीसीटीवी फुटेज और कोसी रेस्तरां और ब्लैक क्लब में उसके शराब पीने के साक्ष्य शामिल हैं। अपराध शाखा के अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट किशोर को वयस्क के रूप में सुनवाई के लिए मानने की उनकी याचिका का समर्थन करती है। उन्होंने कहा इस बीच, जांच से पता चला है कि किशोर के रक्त के नमूने, जो उसकी मां के रक्त के नमूनों के साथ बदले गए थे, को ससून जनरल अस्पताल में जैव-विकल्पा आरंभ के रूप में निटाया गया था। नाबालिग लड़के की मां और पिता, डॉ बंईरत- डॉ अजय दावरे और डॉ श्रीहरि हल्नोर - और एक अस्पताल कर्मचारी, अतुल घाटकांबले, वर्तमान में रक्त के नमूने की अदला-बदली के मामले में उनकी कथित सलिप्तता के लिए जेल में है।

अदालत में सिंघवी का तक... क्या जजों को बदनाम करने अधिकार

नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से गुरुवार शाम को जमानत मिली थी लेकिन शुक्रवार को रिहाई पर रोक लगा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब जोटाले से जुटा घन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने की वक्तेशन बेंच में याचिका लगाई, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी। एएसजी राजू ने कहा कि वे तत्काल रोक की मांग कर रहा हूं। हमारी बात निचली अदालत में नहीं सुनी गई। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेट लगाने की मांग का विरोध किया। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दस फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निदेश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाएगा। वकील सिंघवी ने दलीलें देकर कहा कि जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए? इस बारे में गलत धारणा है। सिर्फ इसलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज जोटाला सभी मांगों का निपटारा नहीं किया जाता है, तब इसके एएसजी राजू को जमानत को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है। यह निंदनीय है, दुःख है। सिंघवी ने कहा कि ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखाता है। निचली अदालत में मामला पांच घंटे चला। राजू ने करीब 3 घंटे 45 मिनट का समय लिया और फिर ट्रायल जज पर दौभे मढ़ दिया। सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलीलें दे कि ईडी की लगता है कि वृ्कि सीएम का मामला है, तब घंटों सुना जाना चाहिए और जज को निबंध लिखना चाहिए।

यादव सरकार में मंत्री शाह ने मदरसों को लेकर दिया बड़ा बयान

खडवा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री शाह ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोई भी शिक्षण संस्थान अगर तिरंगे का अपमान करेगी, यहां राष्ट्रगान नहीं होगा, तब उनका बहुत-कुछ बंद हो जाएगा। उन्होंने यह बात खडवा के हॉली स्पिट कॉन्वेंट स्कूल में कही। शाह ने अंतरराष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर स्कूल में योग किया। गौरतलब है कि जनजातीय कार्य मंत्री शाह दो दिन पहले भी इसी तरह की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री था। तब ये आदेश निकाला था कि हर सरकारी, प्राइवेट स्कूल में झंडा वंदन होगा, जन गण मन होगा। लेकिन उस आदेश में थोड़ी सी कमी रह गई थी। वह आदेश छठवीं से 12वीं तक के विद्यालयों के लिए था। लेकिन इस आदेश को पहली से लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मेरा अनुरोध है। उनकी इस बात ने पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोरी थीं। कैबिनेट और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने जब मदरसों में राष्ट्रगान और ध्वजारोहण अनिवार्य करने की मांग की थी, तब मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नकार दिया था।

नीट पेपर लीक मामले में देशभर में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

नई दिल्ली। भारत में नीट यूजी के रिजल्ट पर हंगामा बपर हुआ है। परीक्षा में धांधली को लेकर मध्यप्रदेश सहित देशभर में कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। मीडिकल व डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम पट्टेस ट्रेटर फॉर यूजी (नीट-यूजी) में हुई गड़बड़ियों के विरोध में र्टूडेंट्स जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भोपाल, दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, तेलंगाना सहित देश भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस मांग कर रही है कि र्टूडेंट्स की चिंताओं का समाधान तत्काल किया जाए। भोपाल में कांग्रेस का धरना - वहीं नीट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को कांग्रेस की युध विंग का भी साथ मिल गया है। भोपाल के रंगशपुरा वीरगढ़ पर कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने एनडीए सरकार का पुतला भी दहन किया। विपक्षी नेता आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। सतारुद दत्त, परीक्षा एजेंसी और अपसर बचाव में बयान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि मध्यप्रदेश में पांच अलग-अलग तरह की परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इन पांच परीक्षाओं में कुल 3 हजार 690 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, इसमें 1 लाख 64 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले थे। आरोप है कि पिछले दिनों ही इंदौर में कांग्रेस नेता अक्षय कांत बम की अगुआई में चलने वाले एक कॉलेज से पेपर लीक हुए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं।

दिल्ली के लोगों को राहत, 27 जून से देश के कई हिस्सों में होगी बारिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिन में दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। आज यानी शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 40 और 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इससे पहले गुरुवार को मौसम विभाग ने कहा था कि हल्की बारिश और आंधी ने दिल्ली में गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ ने गुरुवार को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, जो भीषण गर्मी की चपेट में था। विभाग ने कहा कि अगले चार से पांच दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में लू नहीं चलेगी। अनुमान है कि मानसून 27 जून से तीन जुलाई तक मध्य भारत और उत्तर-



पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में आ जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी

राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और यूपी के कई हिस्सों में 20 जून को लू की स्थिति खत्म हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ और

बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के प्रभाव के तहत, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी यूपी में काफी व्यापक रूप से हल्की बारिश देखी गई है। सुबह 8.30 बजे खत्म होने वाले 24 घंटों में उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश देखी गई और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि हुई।

लू के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद केंद्र ने अस्पतालों को रोगियों की देखभाल के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने के लिए की सलाह दी थी। भीषण गर्मी ने पानी की सप्लाई और बिजली ग्रिडों को प्रभावित कर दिया है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने किया साफ, हज यात्र के दौरान कम से कम 98 भारतीय यात्रियों की अब तक जा चुकी है जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत से हज यात्रियों की मौत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बताया कि इस साल अब तक 175,000 भारतीय तीर्थयात्री हज यात्रा पर गए हैं। अब तक 98 भारतीय तीर्थयात्री हैं जिनकी हज के दौरान मौत हो गई है। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस वर्ष हमारे 175,000 भारतीय पहले ही हज पर जा चुके हैं। अब तक हम अपने 98 नागरिकों को खो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये मौतें प्राकृतिक बीमारी, प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारी और बुढ़ापे के कारण भी हुई हैं।

रणधीर जयसवाल ने बताया कि अराफात के दिन छह भारतीयों की मृत्यु हो गई और चार भारतीयों की मृत्यु दुर्घटनाओं के कारण हुई। पिछले साल हज में मरने वाले भारतीयों का आंकड़ा 187 था। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है।



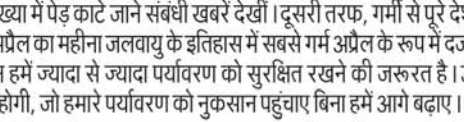
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि यह सात सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल था जिसने 16 से 20 जून तक भारत का दौरा किया। इसका नेतृत्व हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने किया। उन्होंने 18 और 19 जून को धर्मशाला का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने

विदेश मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि मैं परम पावन दलाई लामा पर भारत की स्थिति को दोहराना चाहूंगा। वह एक सम्मानित धार्मिक नेता हैं और भारत के लोग उनका गहरा सम्मान करते हैं। परम पावन को अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के संचालन के लिए उचित शिक्षाचार और स्वतंत्रता दी गई है। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि चीन को कड़ा संदेश देने के लिए मिलकर काम करना भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित में है। उन्होंने कहा कि दोनों लोकतांत्रिक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी पीढ़ी के हथियारों और प्रौद्योगिकी के उत्पादन में वे अग्रणी बने रहें। सांसद माइकल मैककॉल ने यही दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात के दौरान यह बात कही।

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की कोशिश होनी चाहिए : प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वानरा ने भीषण गर्मी और लू के कारण हुई कई मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि विकास इस तरह से होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और लोगों की तरक्की भी हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "कई राज्यों में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने संबंधी खबरें देखीं। दूसरी तरफ, गर्मी से पूरे देश में मौतें हो रही हैं। बढ़ता तापमान नये रिकॉर्ड बना रहा है। इस बार अप्रैल का महीना जलवायु के इतिहास में सबसे गर्म अप्रैल के रूप में दर्ज हुआ है।" प्रियंका गांधी ने कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, " हम सबको मिलकर ऐसे विकास की कोशिश करनी होगी, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें आगे बढ़ाए।



सैक्सटॉर्शन के जरिए सर्वाधिक टगी का शिकार होते हैं युवा और बुजुर्ग

नई दिल्ली (एजेंसी)। आजकल साइबर ला लड़कियों की डीपी लगाकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर दोस्ती करते हैं। इसके बाद व्हाट्स एप पर नंबर लेकर वीडियो कॉल करते हैं। स्कैन कर ही युवती की अश्लील वीडियो अचानक उन पर दिखने लगती है। सामने वाला वीडियो कॉल रिकार्ड कर लेता है। वीडियो दिखाकर वसूली का खेल चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा युवा और बुजुर्ग फंस रहे हैं।

साइबर सेल के एक एक्सपर्ट ने सेक्सटॉर्शन से बचाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करके सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है। वीडियो में दिखाया है कि कैसे साइबर टा रिंकाडेड पोर्न वीडियो को स्क्रीन पर आन करके सामने वाले से अश्लील बात करते हैं। इस जाल में फंसेने वाला शर्म के मारे किसी से शिकायत नहीं करता और रुपये भेजता है। पुलिस ने शर्म छोड़कर साइबर

सेल में शिकायत करने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसी गैंग सक्रिय हैं जो लड़कियों का झंसा देकर युवाओं और व्यापारियों को फंसाते हैं और मोटी रकम वसूलती है।शेखर के एक चर्चित डॉक्टर को युवती बनकर साइबर टा ने फेसबुक पर संपर्क किया। फेंड रिकवेस्ट भेजी। व्हाट्स एप नंबर लिया। तीन दिन तक उनके साथ चैटिंग की। इसके बाद रात में अश्लील वीडियो कॉल करने लगा। न्यूड वीडियो कॉल को रिकार्ड करके डॉक्टर से रुपये मागे। इसके बाद धमकी दी कि उनका वीडियो यूट्यूब और अपलोड का देना। यही नहीं, दिल्ली क्राइम ब्रांच के नाम पर उनके धमकी दी गई। डॉक्टर ने कई बार में कुल 10 लाख रुपये साइबर टा के चार बैंक खातों में जमा कर दिए। ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। आखिर में डॉक्टर ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

महाराष्ट्र में शिंदे के मंत्री के पाला बदलने की खबरों ने मचाई हलचल

- भुजबल, अजित की पत्नी सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन से हैं नाराज

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के खाद्य और नार्गरिक आपूर्ति मंत्री छान भुजबल को महराष्ट्र के बड़े नेताओं में गिनती होती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को तेजतर्रार नेता के रूप में जाना जाता है। भुजबल ने एक बार फिर अपनी पार्टी और महायुति गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बार उन्होंने मराठ आरक्षण और पार्टी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन का मुद्दा उठाया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के खराब प्रदर्शन को लेकर बीजेपी, सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित की एनसीपी जैसे महायुति सहयोगियों में टेंशन बना हुआ है। इस बीच भुजबल के अपनी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ी होंगी। साथ ही अजित पवार के साथ खेला हो सकता है। छान भुजबल ने बीते दिनों इस बात को

नामांकन के लिए भी उत्सुक थे। भुजबल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह परेशान हैं। क्या लोकसभा और राज्यसभा टिकट को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है? इस पर भुजबल ने कहा कि यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए।

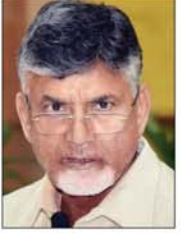
भुजबल को नाराजगी पर अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगी ने खुद उनसे कहा था कि वह नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष समेत कुछ लोग और हमारे करीबी मित्र ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भुजबल के एनसीपी से बाहर निकलने की खबरों का जिन्न कर दिया।

भुजबल ने ऐसे किसी भी कदम से इनकार किया है। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा नामांकन से नाराजगी पर उन्होंने कहा कि वह परेशान नहीं हैं। राजनीतिक दल में रहते समय आपको मिलजुलकर फैसले लेने होते हैं। हर चीज किसी की इच्छा से नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह निर्दलीय नहीं हैं कि अपनी मर्जी से चलेंगे।

छान भुजबल ने कहा था कि उनकी इच्छा सांसद बनने की है और इसीलिए वह नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। वह राज्यसभा

ढाई साल बाद प्रतिज्ञा पूरी होने पर आंध्रप्रदेश विधानसभा लौटे नायडू

अमरावती। मैं सत्ता में लौटने तक सदन से दूर रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ, टीडीपी प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू नवंबर 2021 में तत्कालीन सतारुद वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों के साथ भावनात्मक और तीखी नोकझोंक के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा से चले गए थे। लगभग ढाई साल बाद, नायडू ने शुक्रवार को अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर मुख्यमंत्री के रूप में आंध्रप्रदेश विधानसभा में लौट आए। अपने से बहुत छोटे जगन मोहन रेड्डी के हाथों अपमानजनक हार झेलने के पांच साल बाद, नायडू ने सहयोगी भाजपा और जनधन पार्टी (जेएनपी) के साथ मिलकर अपनी पार्टी को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारी जीत की ओर अग्रसर किया। अपने नवीनतम कार्यकाल में नायडू की प्राथमिकताओं में मुख्यमंत्री अमरावती का विकास है। उन्होंने ग्रीनीफील्ड राजधानी में रुकी हुई परियोजनाओं का जायजा लेने के बाद कहा कि वह अमरावती को लेकर दुविधा में है। उन्होंने अमरावती की स्थिति पर जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी करने और आगे बढ़ने के लिए लोगों से सुझाव लेने का वादा किया। पिछले वाईएसआरसीपी शासन के तहत अमरावती राजधानी शहर परियोजना 2019 से 2024 तक रुकी रही। हालाँकि, सरकार में बदलाव ने राजधानी शहर परियोजना में जान फूंक दी है, क्योंकि नायडू ने घोषणा की है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी।



तमिलनाडु में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 47 हुई, कई गंभीर

- सीएम ने कहा- लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा



चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के कच्छकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 47 पहुंच गई है। 60 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुःख व्यक्त किया और इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्टालिन ने मुत्तकों के परिवार को दस-दस लाख रूपए और अस्पताल में भर्ती लोगों को 50-50 हजार रूपए देने की घोषणा की है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी गोकुलदास की मौजूदगी में गठित एक सदस्यीय आयोग ने मामले की जांच करने की घोषणा की है, जिसकी रिपोर्ट तीन महीने के अंदर पेश करने को कहा गया है। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कच्छकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुःखी हूँ। इस अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया

गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी शोक व्यक्त करते हुए बीमारों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि कच्छकुरिची में अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों से गहरा सदमा लगा है। कई और पीड़ित गंभीर हालत में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और अस्पतालों में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। राज्य के कई हिस्सों में अवैध शराब के सेवन से अक्सर लोगों की दुःखद मौत की खबरें आती हैं। यह अवैध शराब के उत्पादन और खपत को रोकने में हो रही चूक को दूरना है। यह गंभीर चिंता का विषय है।



योग अपनाए जाते तो योगी व निरोगी बनने के साथ समाज में सहयोगी एवं उपयोगी बनने की प्रेरणात्मक ऊर्जा मिलती है। उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 'स्वयं और समाज के लिए योग' थीम पर योग में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण समग्र राज्य में किया गया। नडाबेट में आयोजित राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में खेल, युवा एवं सांस्कृतिक

गतिविधि विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार, सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक अभिषेक पाठक, पूर्व सांसद परबतभाई पटेल, विधायक केशजी चौहान, प्रवीणभाई माळी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 'स्वयं और समाज के लिए योग' थीम पर योग में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण समग्र राज्य में किया गया। नडाबेट में आयोजित राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में खेल, युवा एवं सांस्कृतिक

शेयर बाजार की तेजी थमी, चार दिन बाद गिरे सेंसेक्स-निफ्टी

मुंबई। ब्याज की ऊंची दर को झेलने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका मजबूत है या नहीं, का पता लगाने के लिए कराये जा रहे कारोबार सर्वे की रिपोर्ट जारी होने से पहले विश्व बाजार में आई गिरावट से हतोत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और तेल एवं गैस समेत तेरह समूहों में हुई बिकवाली से आज शेयर बाजार चार दिन बाद गिरकर बंद हुआ।

बीएसई का तीस शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक सेंसेक्स 269.0 अंक लुढ़ककर 77,209.90 अंक रह गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 65.90 अंक टूटकर 23,501.10 अंक पर आ गया। इस दौरान बीएसई का मिडकैप 0.26

प्रतिशत फिसलकर 45,967.07 अंक जबकि स्मॉलकैप 0.06 प्रतिशत बढ़कर 51,936.53 अंक हो गया।

इस दौरान बीएसई में कुल 3987 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2086 में बिकवाली जबकि 1784 में लिवाली हुईं वहीं 117 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह निफ्टी की 32 कंपनियों के शेयरों में गिरावट जबकि 18 में तेजी रही।

बीएसई के 13 समूहों में बकवाली का दबाव रहा। इससे कर्मांडिटीज 0.92, सीडी 0.39, ऊर्जा 1.02, एफएमसीजी 1.08, वित्तीय सेवाएं 0.28, हेल्थकेयर 0.10, इंफ्रस्ट्रक्चर 0.47, यूटिलिटीज 0.22, ऑटो 0.71, बैंकिंग 0.22, कैपिटल गुड्स 0.96, तेल एवं गैस 1.28 और रियल्टी समूह के शेयर 0.75 प्रतिशत टूट गए।



अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट का खूब रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफटीएसई 0.70, जर्मनी का डैक्स 0.54, जापान का निक्केई 0.09, हांगकांग का हेंगसेंग 1.67 और चीन

का शंघाई कम्पोजिट 0.24 प्रतिशत उतर गया।

कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 251 अंक की तेजी के साथ 77,729.48 अंक पर खुला और

लिवाली होने से थोड़ी देर बाद ही 77,808.45 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वहीं, बिकवाली के दबाव में यह कारोबार के अंतिम चरण में 76,802.00 अंक के निचले स्तर तक टूट गया।

अंत में पिछले दिवस के 77,478.93 अंक के मुकाबले 0.35 प्रतिशत की गिरावट लेकर 77,209.90 अंक पर बंद हुआ।

इसी तरह निफ्टी भी 94 अंक बढ़कर 23,661.15 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 23,667.10 अंक के उच्चतम जबकि 23,398.20 अंक के निचले स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 23,567.00 अंक की तुलना में 0.28 प्रतिशत कमजोर होकर 23,501.10 अंक पर आ गया।

इस दौरान सेंसेक्स की गिरावट पर रही प्रमुख कंपनियों में अल्ट्रासिमको 2.22, एलटी 1.78, टाटा मोटर्स 1.74, नेस्ले इंडिया 1.71, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.63, टाटा स्टील 1.37, रिलायंस 1.34, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.17, बजाज फाइनेंस 1.07, आईटीसी 0.89, एसबीआई 0.88, टाइटन 0.88, एशियन पेंट 0.85, एक्सिस बैंक 0.55, सन फार्मा 0.40, एचडीएफसी बैंक 0.22 और टेक महिंद्रा 0.02 प्रतिशत शामिल रही।

वहीं, भारती एयरटेल 2.32, इंफोसिस 1.08, टीसीएस 0.59, जेएसडब्ल्यू स्टील 0.54, एनटीपीसी 0.50, कोटक बैंक 0.48, पावरग्रिड 0.37, एचसीएल टेक 0.26, मारुति 0.20 और विप्रो के शेयर 0.01 प्रतिशत की बढ़त पर रहे।

कुशल वरिष्ठ और मध्यम वरिष्ठ डेवलपरो के बड़े पैकेज के साथ बढ़ रही मांग : स्केलर

नयी दिल्ली। अग्रणी शिक्षा प्रदाता स्केलर की एक रिपोर्ट के अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र में धर्ती करने वाले लोग वरिष्ठ डेवलपर जैसे प्रमुख भूमिकाओं के लिए सक्रिय रूप से उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें कंपनियां 32.04 लाख रुपये प्रति वर्ष का औसत पैकेज और मध्यम वरिष्ठ डेवलपर के लिए 34.69 लाख रुपये प्रति वर्ष का औसत पैकेज प्रदान कर रही हैं।

स्केलर ने यहां जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेवा-आधारित कंपनियों में सिस्टम इंजीनियर और सपोर्ट इंजीनियर की भूमिकाओं से आगे बढ़ने वाले तकनीकी पेशेवरों को अपस्किलिंग के बाद सबसे अधिक वेतन वृद्धि मिल रही है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग क्षेत्रों में उच्च-धुतान वाली भूमिकाएँ भी उच्च माँग में हैं। वरिष्ठ डेटा वैज्ञानिक और वरिष्ठ डेवलपर औसत वेतन पैकेज में सबसे ऊपर हैं और वे 20.28 लाख रुपये वार्षिक और 24.06 लाख रुपये वार्षिक कमा रहे हैं। अपस्किलिंग के

बाद वरिष्ठ मशीन लर्निंग इंजीनियर पदों पर आगे बढ़ने वाले पेशेवरों को सबसे अधिक वेतन वृद्धि मिल रही है, जिसमें औसतन 150 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

बी2के एनालिटिक्स द्वारा मूल्यांकन की गई कैरियर ट्रैजिशन असेसमेंट रिपोर्ट, जो आईआईएम अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट का भी ऑडिट करती है, यह दर्शाती है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से शीर्ष 25 प्रतिशत शिक्षार्थी 48 लाख रुपये प्रति वर्ष का औसत पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, जबकि बीच के 80 प्रतिशत को 25 लाख रुपये प्रति वर्ष का औसत पैकेज मिल रहा है।

डेटा साईंस प्रोग्राम के स्नातकों के लिए यही संख्या क्रमशः 35 लाख रुपये और 18 लाख रुपये वार्षिक है। रिपोर्ट में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी प्रमुख टेक कंपनियों द्वारा इन कौशल वाले प्रतिभाओं की भर्ती करने की प्रवृत्ति का भी पता चलता है। साथ ही एक्सप्रैसबोस, वालमार्ट, ओरेकल, सेल्सफोर्स, सैमसंग और पेपल जैसे अन्य क्षेत्रों के प्रमुख नाम अपस्किलड

पेशेवरों की तलाश कर रहे हैं। यह मांग टीसीएस और कागिनजेंट जैसी कंपनियों और डेलॉयट और ईवाई जैसी पेशेवर सेवा दिग्गजों तक फैली हुई है। स्केलर और इंटरव्यूबिट के सह-संस्थापक अंशुमान सिंह ने कहा स्केलर में हमारा उद्देश्य टेक पेशेवरों को आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। इस प्लेसमेंट रिपोर्ट के निष्कर्ष करियर की संभावनाओं को बढ़ाने और उद्योग की मांगों को पूरा करने में अपस्किलिंग के टोप लाभांशों को रेखांकित करते हैं। जैसे-जैसे उद्योग भर के संगठन तेजी से तकनीकी प्रगति कर रहे हैं, अनुकूलनीय और कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ती जा रही है।

यह प्रवृत्ति 2022 की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुरूप है, जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपस्किलिंग की निरंतर आवश्यकता को दर्शाती है। रिपोर्ट में वृद्धि लगातार विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में कुशल पेशेवरों की निरंतर मांग को दर्शाती है।

यह न केवल व्यक्तियों को अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है, बल्कि एक

अधिक कुशल और भविष्य-रूप टेक कार्यबल में भी योगदान देता है। स्केलर एकेडमी और स्केलर डीएसएमएल (डेटा साईंस एंड मशीन लर्निंग) के अपस्किलिंग कार्यक्रमों के शिक्षार्थियों ने पिछले दो वर्षों में क्रमशः 150 प्रतिशत और 110 प्रतिशत की औसत वेतन वृद्धि हासिल की है, औसत वेतन वृद्धि 23,398.20 अंक के निचले स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 23,567.00 अंक की तुलना में 0.28 प्रतिशत कमजोर होकर 23,501.10 अंक पर आ गया।

अधिक कुशल और भविष्य-रूप टेक कार्यबल में भी योगदान देता है। स्केलर एकेडमी और स्केलर डीएसएमएल (डेटा साईंस एंड मशीन लर्निंग) के अपस्किलिंग कार्यक्रमों के शिक्षार्थियों ने पिछले दो वर्षों में क्रमशः 150 प्रतिशत और 110 प्रतिशत की औसत वेतन वृद्धि हासिल की है, औसत वेतन वृद्धि 23,398.20 अंक के निचले स्तर पर रहा। अंत में पिछले सत्र के 23,567.00 अंक की तुलना में 0.28 प्रतिशत कमजोर होकर 23,501.10 अंक पर आ गया।

कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा



नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यहां आम बजट 2024-25 की तैयारियों के मद्देनजर कृषि संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में कृषि संगठनों और इस क्षेत्र के अर्थशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिये और विचार रखे। वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह बजट पूर्व चौथी बैठक थी।

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव; आर्थिक मामलों, राज्य, वित्तीय सेवाओं और कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इसमें शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में मद्देनजर इसका फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। आम चुनाव के बाद अब फिर से सौतारमण को वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है और वे अब पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू कर दीं।

नव निर्वाचित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र तीन जुलाई तक चलेगा जिसमें शुरू में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जाएगी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ, स्पीकर के चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। राज्यसभा का 26वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और तीन जुलाई तक चलेगा।

एसी उम्मीद है कि संसद का यह सत्र दो चरणों में संपन्न हो सकता है। इसका दूसरा चरण 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल सकता है तथा इसी दौरान वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और इस पर चर्चा कर इसे पारित कराया जायेगा।

श्रीलंका में भी बजेगा हिमट्रेडिशन ब्रांड के उत्पादों का डंका

पालमपुर। जाइका वानिकी परियोजना का अपना ब्रांड हिमट्रेडिशन के उत्पादों का डंका अब पड़ोसी देश श्रीलंका में भी बजेगा।

जाइका परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को खरीद कर जाइका श्रीलंका की टीम के चेहरे प्रफुल्लित हुए। दो दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंचे श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने पालमपुर के समीप गोपालपुर मार्केटिंग आउटलेट से हिमट्रेडिशन ब्रांड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की खरीददारी की। इस दौरान हिमाचली टोपी, शॉल, आचार, चटनी, पत्तल, बैग सहित कई अन्य उत्पादों की खूब बिक्री हुई। गुरुवार को वन मंडल पालमपुर के डूबरे रेंज के तहत चौपाटी महादेव भोड़ा में महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद सत्र का आयोजन किया गया। जाइका इंडिया की प्रोजेक्ट फॉर्मलेशन एडवाइजर इनागाकी युकारा ने हिमाचल में हो रहे कार्यों की सराहना

की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सफल प्रबंधन के मुताबिक जाइका वानिकी परियोजना चल रही है और श्रीलंका की टीम को दो दिनों तक काफी कुछ सीखने को मिला।

श्री युकारा ने कहा कि हिमाचल में जाइका वानिकी परियोजना की सफलता की कहानी अब श्रीलंका में पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जाइका से जुड़े सभी स्वयं सहायता समूहों को मेहनत रंग ला रही है और आजीविका सुधार के साथ ही आय सृजन में सफलता मिल रही है। उन्होंने हिमट्रेडिशन ब्रांड को भी तारीफ की। संवाद सत्र के पश्चात श्रीलंका की टीम ने जयसिंहरूप रेंज के अंतर्गत नर्सरी फार्म शिवनगर का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्य परियोजना निदेशक समीर रस्तोगी, परियोजना निदेशक श्रेष्ठा नंद, प्रोग्राम मैनेजर विनोद शर्मा, डा. कौशल्या कपूर, प्रिया, शिवानी वालिया समेत वन विभाग और जाइका वानिकी परियोजना की टीम मौजूद रही।

वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित होगी 'पीतल नगरी'

मुरादाबाद को अगले सात साल में विकसित करने के लिए योगी सरकार ने खींचा खाका

लखनऊ। प्रदेश के प्रत्येक जिले को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा करने में जुटी योगी सरकार पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद के लिए महायोजना 2031 लेकर आई है।

इसके अंतर्गत जहां एक तरफ शहर का विस्तार और विकास सुनिश्चित किया जाना है, वहीं इसकी पहचान और ओडीओपी में शामिल पीतल हैंडीक्राफ्ट के निर्माण और निर्यात उद्योग को भी बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि मुरादाबाद को वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित किया जाए। यहां पीतल उद्योग से जुड़े आर्टिजन के लिए हस्तशिल्प ग्राम बनाने के साथ ही मेगा एम्प्लॉयमेंट पार्क के निर्माण का प्रस्ताव भी है। यहीं नहीं औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के जरिए मुरादाबाद के औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों ने मुरादाबाद महायोजना 2031 के

प्रस्तुत किया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का होगा विकास

महायोजना में इस बात का उल्लेख है कि वर्तमान में 13,14,914 की आबादी वाले शहर की जनसंख्या 2031 में तकरीबन 16,66,404 हो जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार का निर्माण, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास किया जाना है। साथ ही साथ नगर के पर्यावरण का संरक्षण करते हुए सतत और नियोजित विकास को बढ़ावा देना है।

इसमें ट्रेफिक प्लान को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया जाएगा। ट्रेफिक डीकंजेशन के लिए 60 मीटर चौड़े रिंग रोड का प्रावधान है। वहीं विकास क्षेत्र से बाहर एसीजेंड को नगर के अंदर मौजूद औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने के

लिए 36 मीटर चौड़े औद्योगिक गलियारे का भी विकास किया जाएगा। 1200 हेक्टेयर में मेगा टाउनशिप शिवालिक का प्लान

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में मुरादाबाद में हस्ताशिल्प ग्राम, मेगा एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर, इंफ्रस्ट्रक्चर लॉजिस्टिक पार्क, नॉलेज सिटी व मेडीसिटी के साथ ही 55 एकड़ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण की बात भी कही गई है।

इसके अलावा औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए कौशल विकास केंद्र, निर्यातकों व निवेशकों की सुविधा के लिए ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर, 1200 हेक्टेयर में मेगा टाउनशिप शिवालिक और 130 हेक्टेयर में औद्योगिक व मिश्रित तथा 50 हेक्टेयर में आवासीय आत्याधुनिक टाउनशिप का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स सिटी, आयुष पार्क, शुरारकेन प्रोसेसिंग क्लस्टर, कैटल

कॉलोनी, मल्टी मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर का भी प्रस्ताव है। महायोजना 2031 के लिए मुरादाबाद में वर्तमान में 18017 करोड़ रुपये की शॉर्ट टर्म, 13027 करोड़ रुपये की मिडियम टर्म और 10749 करोड़ रुपये की लॉन्ग टर्म परियोजनाएं संचालित हैं।

दुनियाभर में होता है पीतल से बनी कलाकृतियों का निर्यात

बता दें कि मुरादाबाद जोकि पीतल नगरी के रूप में विख्यात है और यहां के पीतल उत्पादों पर बने डिजाइन संस्कृति, विरासत, इतिहास और विविधता को विश्वभर में प्रदर्शित करते हैं।

इन वस्तुओं को सजाने के लिए उपयोग किये जाने वाले पैटर्न और डिजाइन विभिन्न स्रोतों से प्रेरित होते हैं, जिनमें हिन्दू देवी-देवताओं से लेकर मुगलकाल की पेंटिंग तक शामिल हैं। यहां से विश्वभर में पीतल के उत्पाद निर्यात किये जाते हैं।

पिछले वर्ष डीआरआई ने जब्त कीं 3500 करोड़ की प्रतिबंधित सामग्रियां

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने पिछले वित्त वर्ष में तस्करी के 623 मामलों का पता लगाया और 3500 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित सामग्रियां जब्त कीं। जब्त की गई सामग्रियों में सबसे ज्यादा ड्रग्स और सोना बरामद हुआ।

दरअसल डीआरआई के प्रधान महानिदेशक मोहन कुमार सिंह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की एक संगोष्ठी को संबोधित किया। देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग होती है। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त चैन को तोड़ना बहुत जरूरी है और यह सबसे बड़ी चुनौती भी है। डीआरआई ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई सारी प्रतिबंधित सामग्रियों का पता लगाया। डीआरआई के प्रधान महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने



बृहस्पतिवार को कहा, आपूर्ति शृंखलाओं में घुसपैठ तस्करी पर अंकुश लगाने में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इन वस्तुओं की तस्करी के लिए हवाई यात्रियों, कोरियर और डाक कार्गो का इस्तेमाल किया जाना भी चिंता का विषय है। डीआरआई ने 623 तस्करी के मामलों का पता लगाया था। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 2 मामले सामने आते थे। तस्करी में डीआरआई ने 3,500 करोड़ रुपये जब्त किये थे।

शार्ट न्यूज

एपीवाई पूरे देश में व्यापक रूप से लागू

नयी दिल्ली। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को पूरे देश में व्यापक रूप से लागू किया गया है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और इस योजना के तहत कुल सकल नामांकन 20 जून 2024 तक 6.62 करोड़ को पार कर गया है जिनमें 1.22 करोड़ से अधिक नए अभिदाता शामिल हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडी) के अध्यक्ष डॉ दीपक महानी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 1.22 करोड़ से अधिक नये नामांकित हुए हैं। इस योजना ने सकल नामांकन में 24 प्रतिशत की प्रगति वित्त वर्ष 2023-24 में हासिल की। एपीवाई देश की महिला आबादी और युवा पीढ़ी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वित्तवर्ष 2023-24 में कुल नामांकन में से 52 प्रतिशत महिला अभिदाताएँ हैं और कुल सकल नामांकन में से 70 प्रतिशत अभिदाता 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग से हैं। डॉ महानी ने पीएफआरडी द्वारा आयोजित वार्षिक एपीवाई सामान कार्यक्रम में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफआरडी / डीएफएस द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं वार्षिक लक्ष्य के लिए 49 एपीवाईएसपी (बैंक), 9 एएलबीसी और देश की पांच शीर्ष शाखाओं के साथ ही एलडीएम को सम्मानित किया गया।

2000 टन गैर बासमती चावल अफ्रीकी देशों को निर्यात; एक साल में गेहूँ के दाम दो फीसदी बढ़े

दो अफ्रीकी देश मलावी और जिम्बाब्वे को दो हजार टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिये होगा। वहीं फरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई, 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है। हालांकि अनुरोध पर कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की मंजूरी है। भारत ने पहले भी नेपाल, कैमरून, कोट डी आइवर, गिनी, मलयेशिया, फिलीपीन और सेशेल्स जैसे देशों को ऐसे निर्यात की अनुमति दी है। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले एक साल में गेहूँ की कीमतें दो फीसदी तक बढ़ी हैं। गेहूँ की कीमतों में स्थिरता लेकर आने के लिए सरकार उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप करेगी। इसके लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद सरकारी बयान के अनुसार उन्होंने अधिकारियों को गेहूँ की कीमतों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस समय गेहूँ की औसत कीमत 30.99 रुपये है, जो कि एक साल पहले 28.95 रुपये प्रति किलो थी। वहीं आटे के दाम 34.29 रुपये से बढ़कर 36.13 रुपये हो गए हैं।

आईपीओ में बढ़ रही धांधली पर लगेगी रोक

सेबी ने आईपीओ में बढ़ रही धांधली पर रोक लगाने के लिए कर्मर कस ली है। इसके लिए निष्पत्ती के स्टॉक एक्सचेंजों को प्री-ओपन कॉल नीलामी सत्र में दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। आईपीओ शेयरों के कारोबार में लगातार धांधली बढ़ रही है। इस बढ़ती धांधली पर अब रोक लगाई जाएगी। इसके लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को प्री-ओपन कॉल नीलामी सत्र में दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। आईपीओ शेयरों के कारोबार में बढ़ती धांधली पर रोक लगाई जाएगी। इसके रोकने के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को प्री-ओपन कॉल नीलामी सत्र के दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। जारी निर्देश के तहत निर्यात के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को प्री-ओपन कॉल नीलामी सत्र में दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे तक होगा। इसमें 45 मिनट ऑर्डर एंटी, बदलाव और रद्दीकरण के लिए होगा। 10 मिनट ऑर्डर मिलान और व्यापार पुष्टिकरण के होंगे। 15 मिनट प्री-ओपन से सामान्य सत्र में जाने के लिए होगा। बता दें कि सेबी ने हाल में अपनी जांच के दौरान पाया कि कुछ आईपीओ शेयरों के लिए प्री-ओपन सत्र में 10 बजे

PROPRE LUXURY

Real Estate Advisor

Earn by real estate investment with
high yield and capital growth..

BOOK NOW

www.propreluxuryrealestate.com

proppre
Luxury Real Estate